भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1164
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)
महिलाओं का सशक्तीकरण

1164. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में लैंगिक विचारों को शामिल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण महिलाओं को, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व, ऋण तक पहुंच और नेतृत्व की भूमिकाओं के संदर्भ में, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है ;
और

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति है कि ग्रामीण युवाओं को उभरती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए कौशल्य और अवसर प्रदान किए जाएं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता देता है। लैंगिक कार्यक्रम को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम स्वीकार करता है कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण से पूर्व लैंगिक असमानता का समाधान आवश्यक है। यह कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की क्षमता का निर्माण करता है ताकि इसके संचालन में महिलाओं को एकीकृत किया जा सके और महिला समूहों के लिए सामुदायिक स्तर पर सहायता की एक संरचना बनाई जा सके जो लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करें और उन पर कार्रवाई

करें। इन प्लेटफार्मों पर प्रशिक्षण और परिप्रेक्ष्य-निर्माण इनपुट की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाती है और जेंडर काडर के प्रशिक्षित पूल द्वारा ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय महासंघ (सीएलएफ) के तहत सामाजिक कार्य समितियों (एसएसी) को प्रदान की जाती है। ये निकाय मुख्य रूप से भेदभाव के मुद्दों की पहचान, मान्यता और समाधान करके समाज में महिलाओं की स्थिति और दर्जे को ऊपर उठाने के आधार वाक्य पर कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लैंगिक अभियान (नई चेतना) के माध्यम से कई बड़े पैमाने पर पक्ष समर्थन भी करता है। डीएवाई एनआरएलएम महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सशक्त बना रहा है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त ऋण इस प्रकार हैं:

1.	2019-20	-	70,977 करोड़ रुपए
2.	2020-21	-	84,717 करोड़ रुपए
3.	2021-22	-	1,20,477 करोड़ रुपए
4.	2022-23	-	1,57,370 करोड़ रुपए
5.	2023-24	-	2,07,820 करोड़ रुपए

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत यह आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम का अनुरोध किया हो। महात्मा गांधी नरेगा रूप से लैंगिक-तटस्थ योजना है जो पुरुषों के साथ मजदूरी समानता, महिलाओं के लिए मजदूरी दरों की अलग अनुसूची का प्रावधान, क्रेच की सुविधा, बच्चों के लिए कार्यस्थल पर शेड और बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अभिसरण में महिला मेट्स भी बनाए गए हैं, जो महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं। 2019-20 से 2023-24 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी दर (कुल में से महिला श्रम-दिवस का प्रतिशत) निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
महिलाओं की भागीदारी दर (%)	54.78	53.19	54.82	57.47	58.9

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत महिलाओं के लिए एक विशेष योजना यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) लागू कर रहा है। आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत केंद्रीय पेंशन राशि प्रति लाभार्थी प्रति माह 300 रुपये है। राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से कम से कम इतनी ही राशि का योगदान करने की सलाह दी गई है। आवेदक 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा होनी चाहिए। आवेदक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर, लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपये की बढ़ी हुई सहायता मिलती है। वर्तमान में विधवा लाभार्थियों को राज्य पेंशन राशि के आधार पर 300/- से 2800/- रुपये के बीच पेंशन मिल रही है , जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। वर्तमान में , सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस योजना के तहत अधिकतम सीमा 67.36 लाख तय की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआरएलएम के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल्य विकास में दो कल्याणकारी कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है जो इस प्रकार है :-

- i. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू -जीकेवाई) 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल्य विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल्य प्रदान करता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है , इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करता है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत, 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों में प्रशिक्षित और नियोजित कुल अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों का विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	कुल		महिलाएं	
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
2019-20	247177	150214	126691	66440
2020-21	38289	49563	19685	22640
2021-22	97006	45612	58443	26040
2022-23	231491	158078	133519	92065
2023-24	199524	157456	122250	94684

2024-25 दिसंबर'24 तक	69086	53810	43228	33646
-------------------------	-------	-------	-------	-------

ii. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना महिलाओं सहित सभी श्रेणियों के लिए लागू है। 18-45 वर्ष की आयु के किसी भी बेरोजगार युवा , चाहे उसकी जाति , पंथ, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो , स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने की योग्यता रखने वाला और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। आरएसईटीआई के तहत पिछले 5 वर्षों में प्रशिक्षित और नियोजित कुल अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	कुल		महिलाएं	
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
2019-20	384025	281645	274135	202010
2020-21	255141	185234	206794	138538
2021-22	314114	256429	257107	212400
2022-23	409802	325880	331898	272977
2023-24	451419	350272	360318	290392
2024-25 (दिनांक 31-12- 2024 तक)	471968	299356	382796	249717

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं में सामान्य रूप से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि विधवा/अविवाहित/अलग रह रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर , आवास का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। राज्य केवल महिला के नाम पर आवास आवंटित करने का विकल्प भी चुन सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी -पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक के तहत , योजना के दिशानिर्देशों में नियोजन और कार्यान्वयन के दौरान महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित चार सदस्यीय वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) में कम से कम 1 महिला सदस्य होनी चाहिए। इसी तरह , गांव स्तर पर परियोजना विकास

कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा गठित 11 सदस्यीय वाटरशेड समिति में कम से कम दो महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए।

जहां तक भूमि स्वामित्व का सवाल है, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करके, यह योजना सुनिश्चित करती है कि महिलाओं, जिनमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं भी शामिल हैं, के पास सुरक्षित भूमि का स्वामित्व हो। इसके अलावा, जैसा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बताया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों और पंचायतों के अध्यक्षों के कुल कार्यालयों में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। हालाँकि, 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने इससे भी आगे बढ़कर अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और 2 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् "लक्षद्वीप" और "दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव" ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान (अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई से कम आरक्षण नहीं) लागू होता है।

सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। इस मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग से वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन करने, महिला तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि की बुराइयों से निपटने के लिए राज्यों को परामर्श भी जारी किए हैं।